5.00 P.M

GOVERNMENT BILLS (*Contd.*)

The Appropriation (No. 2) Bill, 2008

And

The Finance Bill, 2008— *Contd.*

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI: Function of price list management of futures market grows from the farmers, allows the farmers to hedge against adverse price movement thereby, avoiding distress selling of their produce in the physical market. Similarly, the price discovery mechanism brings efficiency in the agricultural market in a process by generating stable price on the life of a crop. It needs to be understood that commodity futures market are performing an auxiliary function to the physical market which is already being taxed. Hedging in futures market is covering the price risk. Therefore, this will amount to double taxation of the same transaction. There is no tax on other assets of classes sensitive to the transaction cost, such as commodities, namely, bond markets, call money markets, forex markets, gold exchange markets and market traded fund. In case of bonds the tax once levied had to be withdrawn hastily on account of drop in volume and if this futures market is drawn out of existence the farmer's community will wage a war and we will have to react very strongly against the return of the old low cost of economy kind of measures. Thank you.

श्री हरीश रावत (उत्तराखंड): उपसभापति महोदय, आज जब इस वर्ष के बजट के प्रस्तुतीकरण के बाद सारी वित्त नीतियों और वित्त प्रस्तावों पर यह सदन आखिरी मुहर लगाने जा रहा है, मैं माननीय वित्त मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि इस बजट के प्रस्तुत होने के बाद, हमारी अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में विश्वास पैदा हुआ है और हर क्षेत्र निश्चित तौर पर सकारात्मक दृष्टिकोण से respond कर रहा है। मैं इस संदर्भ में विशेष तौर पर कृषि क्षेत्र का उल्लेख करना चाहूंगा। पिछले कुछ वर्षों से हमारा किसान विशेष तौर पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मैदानी इलाकों का किसान, जो सरकारी, खरीद केन्द्रों पर अपना उत्पाद बेचने से परहेज करने लग गया था, इस वर्ष उसने लाइन लगाकर आपके खरीद केन्द्रों में, आपके लक्ष्य के अनुरूप अपने खाद्यान्न की बिक्री की है। यदि आज हमारे गेहूं के भंडार भरे हैं, तो इसका सीधा अर्थ है कि किसानों तक सरकार का संदेश सकारात्मक रूप में गया है और उनमें विश्वास का सृजन हुआ है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि किसानों में बढ़े हुए इस विश्वास को आगे बढ़ाने की चुनौती को उन्हें स्वीकार करना चाहिए। कुछ और नीतियां, जिनसे कृषि क्षेत्र में हम अपने लक्ष्यगत विकास की दर को प्राप्त कर सकें, इसके लिए कदम उठाने की आवश्यकता है।

उपसभापति जी, ऋण माफी को लेकर बहुत कुछ कहा गया और ऋण माफी की घोषणा के साथ कई राजनीतिक दलों की परेशानी पर बल भी पड़े, उनको चिंता भी हुई और एक प्रमुख राजनीतिक दल ने किसान चौपालों के जरिए विरोध की नौटंकी का भी प्रयास किया। यह अलग बात है कि इनके उस प्रयास में लोगों का समर्थन नहीं जुटा, मगर उनको समर्थन मिला या नहीं मिला, हमको कुछ ऐसे कदम उठाने की आवश्यकता है, जिससे किसानों के अंदर और अधिक विश्वास पैदा हो सके। मैं इस संदर्भ में उन किसानों का विशेष तौर पर उल्लेख करना चाहूंगा, जिन किसानों ने समय पर अपना ऋण अदा किया है। अधिकांश ऋण या तो प्राइवेट लेण्डर्स का है या सहकारी संस्थाओं का है, जिसे किसानों ने लिया है। सर, हम सब लोग इस बात से वाकिफ हैं कि सहकारी संस्थाओं में जो ऋण वितरित किया जाता है, वर्ष के आखिर में सहकारी संस्थाओं के लोग आते हैं, ब्याज लेते हैं और ब्याज ले करके केवल entry change कर ली जाती है इस साल की ऋण की राशि अगले साल में चढ़ा ली जाती है। ऐसे सारे किसान इस समय यह महसूस कर रहे हैं कि वे आज वंचित हो गए हैं। जिन किसानों ने समय पर ऋण की अदायगी की है, उन किसानों के लिए एक प्रोत्साहन पैकेज माननीय वित्त मंत्री जी को announce करना चाहिए, क्योंकि मेरी कम से कम यह धारणा है कि यह ऋण माफी एक पहली किस्त है और इसके follow up measures के रूप में कुछ और कदम माननीय वित्त मंत्री जी आने वाले समय में उठाएंगे, ऐसा मेरा मानना है।

सर, मैं इस संदर्भ में दूसरा सुझाव यह देना चाहता हूं कि जो criteria है, आपने दो हेक्टेयर तक के किसान की ऋण

माफी की घोषणा की है, लेकिन अर्सिचित खेती वाला किसान, जिनका रकबा दो हेक्टेयर से ज्यादा है, वे अपने को deprived महसूस कर रहे हैं, वे वंचित महसूस कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि आपकी कृपा दृष्टि, भारत सरकार की कृपा दृष्टि उनके ऊपर नहीं गई है। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा, जब आज हम छाती ठोक कर रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूजी के साथ आगे बढ़ रही है, तो उसमें ऐसे अर्सिचित किसानों को भी सम्मिलित करना चाहिए, क्योंकि किसानों में यदि सबसे बुरी स्थिति में कोई है तो वह अर्सिचित खेती वाला किसान है। यही किसान ऐसे हैं, जहां हमारी एग्रिकल्चर का 62 परसेंट से ज्यादा work force खपती है। इतने बड़े हिस्से को वंचित हिस्से के रूप में रखना अनुचित रहेगा, ऐसा मेरा मानना है।

सर, मैं दूसरा सुझाव ब्याज दर घटोतरी के रूप में देना चाहता हूं। कर्नाटक के चुनाव में प्रत्येक राजनीतिक दल यह दावा कर रहा है कि एग्रिकल्चर लोन पर ब्याज दर को घटाकर चार प्रतिशत पर लाया जाएगा। यह एक प्रकार का चुनावी मुद्दा बन गया है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में दूसरे राज्यों के चुनावों में भी इसी तरह की प्रवृत्ति आगे बढ़ेगी। यदि ब्याज दर का मामला राजनीति और चुनाव का विषय हो गया, तो इससे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के Cooperative क्रेडिट सिस्टम पर भविष्य में गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि ब्याज दर के विषय में एक स्पष्ट राष्ट्रीय नीति अपनाई जानी चाहिए। पूरे देश के अंदर इस मामले में एक सहमति है कि कृषि ऋण पर ब्याज दर घटाई जाए और उसको घटाकर चार प्रतिशत के आसपास लाया जाए। इस पर आपको विचार करने की आवश्यकता है। किसानों के मन में आपके प्रति बहुत अच्छी धारणा पैदा हुई है। राशिद अली साहब मेरे दोस्त हैं, ये मेरी इस बात की ताकीद करेंगे। इस समय आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान के पास जाइए, तो वह हम लोगों से कहते हैं कि थारो चिदम्बरम तो किसान लागे, कहने का मतलब यह है कि तुम्हारा चिदम्बरम तो हम किसानों में से लगता है। लोग आपके गोत्र को खोज रहे हैं कि आप किस प्रांत के हैं। उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों को लग रहा है कि वित्त मंत्री हमारे दुख के साथ, हमारी तकलीफ के साथ सम्मिलित हैं। आपने शायद अपने पहले बजट को प्रस्तुत करते समय कहा था, जब किन्हीं सुझावों को ले करके कुछ लोगों ने बीच में टोका-टोकी की, तो आपने कहा कि मैं हूं न। आज इस शब्द को सार्थक करने का सबसे बड़ा अवसर आ गया है। देश के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है, हमारी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा है, मान्यवर, मैं समझता हूं कि हमारी अर्थव्यवस्था के cumulative प्रभाव के कारण देश की आबादी का 40 प्रतिशत हिस्सा आज ऐसी स्थिति में आ गया है कि उसके ऊपर price rise का असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन साठ प्रतिशत हिस्सा ऐसा है, बढ़ती हुई कीमतों से जिसके होश फाख्ता हो रहे हैं, विशेष तौर पर उन लोगों के विषय में, जिनकी परचेजिंग पावर सरकार की अपनी कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार बीस रुपया प्रतिदिन से ज्यादा नहीं है। ऐसे लोगों को, जिनको नेशनल सैम्पल सर्वे ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर वे नौ रुपए से ज्यादा प्रतिदिन खर्च करने की स्थिति में नहीं है, जिनके पास कोई कमाने वाला नहीं है। मैं एक छोटे से गांव से आता हूं, आज से दस साल पहले उस गांव में पांच परिवार ऐसे थे, जो पूरे तरीके से राजकीय सहायता पर निर्भर करते थे, मगर आज वह संख्या बढ़कर दस हो गई है। एक तरफ सम्पन्नता बढ़ रही है और दूसरी तरफ विपन्नता भी उतनी ही बढ़ रही है। इस दायरे को घटाना पड़ेगा। पिछले दिनों योजना आयोग के एक अध्ययन में कहा गया है कि नक्सलवाद के बढ़ते हुए प्रभाव का कारण लैंड रिफॉर्म्स का लागू न होना और आर्थिक असमानता का ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ना भी है। नेपाल के अंदर माओवाद के विस्तार के उद्भव के पीछे यही कारण रहा है। Ambanis दुनिया के नंबर एक हो जाएं, हमें खुशी है। हमारी कंपनियां दुनिया की दूसरी बड़ी-बड़ी कंपनियों का अधिग्रहण करें, हमें खुशी है। जब हम अखबारों में पढ़ते हैं कि भारत में millionaires की संख्या बढ़ रही है, तो खुशी होती है, लेकिन दूसरी तरफ तकलीफ होती है कि तीस प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा विपन्नता की श्रेणी में है। वह अपने पांवों पर खड़ा होने की स्थिति में नहीं है। उसके लिए हमें कुछ न कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। उसके लिए पी॰डी॰एस॰ के अंदर आप कुछ ऐसे उपाय कीजिए, कुछ इस तरीके के उपादान कीजिए, ताकि ऐसे वर्गों के ऊपर महंगाई की मार उतनी घातक न हो सके, जितनी घातक इस समय वह दिखाई दे रही है, जितनी घातक वह लग रही है। हमारे सोशल सिक्योरिटी सिस्टम को और ज्यादा strengthen करने की जरूरत है। उसको और ज्यादा प्रभावी बनाने की जरूरत है। आपने बहुत सारी योजनाएं इस दिशा में लागू की हैं, समय के अभाव में इस समय उन सबको यहां पर recollect करना मेरे लिए कठिन है, लेकिन एक-दो ऐसी योजनाओं का मैं उदाहरण देना चाहूंगा। आपकी बड़ी कृपा है, आपने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन दो सौ रुपए से बढ़कर चार सौ रुपया केंद्र सरकार देगी, राज्य भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन ऐसा असहाय वृद्ध, जिसका कोई पालनकर्ता नहीं है, उसके लिए चार सौ रुपया अपनी जीविकायापन के लिए माननीय वित्त मंत्री महोदय, पर्याप्त नहीं है। यह राशि कम

से कम एक हज़ार रुपए होनी चाहिए। जब आज भारत की विकास दर नौ प्रतिशत के आसपास है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में यह और आगे बढ़ेगी, जब हम कह रहे हैं कि हमारी एक सबल अर्थव्यवस्था है, तो ऐसी स्थिति में हम सबसे कमज़ोर को यदि भागीदार नहीं बनाएंगे, तो किसको बनाएंगे? एक असहाय वृद्ध को भागीदार नहीं बनाएंगे तो किसको भागीदार बनाएंगे?

मान्यवर, छत देने के लिए हमारी एक इन्दिरा आवास योजना है, उस योजना के तहत हम लोगों से यह उम्मीद कर रहे हैं कि वे तीस हज़ार रुपए में अपना घर बना लेंगे, एक कमरा, बाथरूम और रसोईघर, क्या यह संभव है? कहां से वह गरीब लाएगा? हम मकान किसको देते हैं? जिसके पास अपने पांवों पर खड़ा होने के लिए कुछ नहीं है, कहीं से इमदाद नहीं है, तो उसको इतनी इमदाद तो दे दी जाए कि वह अपना घर बना सके। हमारे पर्वतीय क्षेत्रों के लिए आपने थोड़े से मानकों को शिथिल किया है, सैंतीस हज़ार रुपया किया है, लेकिन सैंतीस हज़ार रुपए से तो वहां ज़मीन समतल नहीं होती है। मान्यवर, मैं आपके सम्मुख माननीय वित्त मंत्री जी से इस बात का भी उल्लेख करना चाहूंगा कि पर्वतीय क्षेत्रों के लिए वित्तीय सहायता के मानकों को और ज्यादा शिथिल करने की जरूरत है। देश के बीस प्रतिशत पर्वतीय क्षेत्रों के लिए हमारी धारणा में परिवर्तन आना चाहिए, एक बड़ा परिवर्तन आना चाहिए। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना हम बिना हिमालय को अपने साथ रखे हुए नहीं कर सकते। हिमालय की सेवा-सुश्रूषा हमको ठीक से करनी पड़ेगी। ऐसा लगता है कि हिमालय की आवाज़ योजना आयोग में भी कमज़ोर हो गई है। वित्त मंत्रालय में भी कमजोर हो गयी है। इसलिए कुछ इस तरीके का मकैनिज्म होना चाहिए कि वहां के लिए योजनाओं के निर्धारण के वक्त हम उसी तरीके से धनराशि का मात्राकरण कर सके, जिस तरीके से हम स्पेशल कम्पोनेंट की योजनाओं के अंतर्गत करते हैं। भारत सरकार के ऐसे बहुत से मंत्रालय हैं जिनका लाभ वहां के इनफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में लिया जा सकता है जैसे रेल मंत्रालय है, सिविल ऐविएशन का मंत्रालय है, शिपिंग का मंत्रालय है और अन्य कई मंत्रालय हैं जिनका लाभ पर्वतीय क्षेत्र नहीं उठा पाते हैं। आखिर वहां रहने वाले लोगों का भी कुछ हक बनता है। मेरा माननीय वित्त मंत्री महोदय से आग्रह है कि योजना आयोग के साथ कुछ इस तरीके की नीति तय होनी चाहिए, कुछ इस तरीके का सामन्जस्य स्थापित होना चाहिए कि माउंटेन डेवलपमेंट की भारत सरकार की एक स्पष्ट नीति बने, एक खाका बने। मैंने डॉ कर्ण सिंह साहब को कई बार सुना है। उन्होंने कहा कि जो मध्यवर्ती हिमालय है, उसके लिए सेंट्रल हिमालयन डेवलपमेंट अथॉरिटी बननी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के लिए हमारा मंत्रालय है। कुछ इस तरीके का को-ऑर्डीनेशन होना चाहिए क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की समस्याएं दीगर प्रकार की हैं। मध्य हिमालय, जो बायो-डायवर्सिटी का एक प्रकार से खजाना है, जहां हमारी जैविक सम्पदा अकूत रूप से विद्यमान है, जो दुनिया का सबसे बड़ा water reservoir है, आप उसकी सेवा के लिए जो कदम उठाएंगे, उसका पुख्ता लाभ पूरे देश को प्राप्त होगा। इसलिए माउंटेन डेवलपमेंट की एक स्पष्ट नीति भारत सरकार को निर्धारित करनी चाहिए और उसके लिए धन देने के मामले में भारत सरकार को उदारता का परिचय देना चाहिए।

मान्यवर, मैं एक छोटा सा और अनुरोध माननीय मंत्री जी से करना चाहूंगा। बजट प्रस्तुत करने के बाद एक बड़ी प्रभावी रिपोर्ट आयी है जिसका उल्लेख यहां पर हमारे कई दोस्तों ने किया। वह है – पे कमीशन की रिपोर्ट। हम आपके आभारी हैं कि आपकी सरकार ने छठे वेतन आयोग को नियुक्त किया। उस आयोग ने बहुत समय पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। लेकिन आज उस रिपोर्ट को लेकर सब तरफ आलोचना हो रही है। चाहे हमारे आर्म्ड फोर्सिज़ का पक्ष हो, पैरा-मिलिट्री फोर्सिज़ का पक्ष हो, रेलवे का हो या सेक्रेटरिएट के इम्प्लॉइज़ का हो, आज सब तरफ लोगों में बेचैनी है। उस बेचैनी का सबसे बड़ा कारण यह है कि इस पे-कमीशन से यह उम्मीद की गयी थी कि वह न्यूनतम और अधिकतम वेतनमानों के बीच में अंतर को कम करने का प्रयास करेगा। पांचवें वेतन आयोग ने यह अपेक्षा की थी, उसने अपनी रिपोर्ट में भी इस बात का उल्लेख किया था कि इस काम को हम नहीं कर पाए हैं, इस काम को आने वाला पे-कमीशन पूरा करेगा। हमारा सौभाग्य है, इस देश के सैलरीड क्लास का यह सौभाग्य है कि चौथे पे-कमीशन की संस्तुतियों को लागू करने में माननीय चिदम्बरम साहब का हाथ रहा है, उन्हें इसका अवसर मिला है। इसी प्रकार वित्त मंत्री के रूप में पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को आप ही ने लागू करवाया था, जिसने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों में आपकी लोकप्रियता को काफी बढ़ाया है। लेकिन जो छठा वेतन आयोग आया है, इसके संबंध में करेक्टिव स्टेप उठाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गयी है, ताकि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों से लोगों में जो तकलीफ है, जो कष्ट है, वह कम हो सके। सर, क्लास-डी और सी से लेकर ज्वाइंट सेक्रेटरी लैवल तक जो एक्चुअल पे इन्क्रीज़ है,

वह 14 प्रतिशत से 28 प्रतिशत तक है। वहीं ऊपर के दर्जे में, इससे ऊपर जो ज्वाइंट सेक्रेटरी ऐंड अबव के पद हैं, उनमें वह वृद्धि चालीस से लेकर साठ प्रतिशत तक है। मैं कैबिनेट सेक्रेटरी और आर्म्ड फोर्सिज़ के चीफ आदि के लम्प सम पे के विषय में नहीं कह रहा हूं। महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि इस समय जो यह 1:12 का अंतर है, इसको घटाकर 1:8 पर लाने की जरूरत है। इसके विषय में बहुत स्पष्ट निर्देश कैबिनेट सेक्रेटरी महोदय की अध्यक्षता में जो कमेंटी आपने बनायी है... । उस कमेटी को देने की जरूरत है। लोग आशंकित हैं, क्योंकि लोगों का, कर्मचारियों का यह मानना है, मैं समझता हूं इस सदन के हर पक्ष के पास लोग जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। यह फिर लम्बे अंतराल के बाद दिखाई दे रहा है कि केन्द्र सरकार के कर्मचारी जगह-जगह बाहर निकल करके अपना असंतोष जाहिर कर रहे हैं और लोगों को यह लग रहा है कि कैबिनेट सैक्रेटरी शायद उनके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। मेरे दिल में उनके लिए बहुत सम्मान है। मगर इस संदर्भ में इस अंतर को एक बारह के बजाए घटाकर एक आठ लाया जाए और उसके लिए उपाय किए जाएं, ऐसे आपको स्पष्ट तौर पर निर्देश देने पड़ेंगे। मेरा आपसे दूसरा आग्रह है कि यदि इसमें कोई विलम्ब हो रहा है तो उनको अंतरिम सहायता के रूप में रिलीफ देंगे, जो उनकी पे में एडजस्टेबल होगी। यह तो उनको दे डालिए, क्योंकि कर्मचारियों की बैचेनी बढ़ रही है। आपने उनके लिए बहुत बड़ा कदम उठाया, जिस कदम का जिक्र नहीं हो पाया। आपने जिस तरीके से डायरेक्ट टैक्सेज में रिलीफ दी, हर वर्ग को रिलीफ दी, उसके लिए आप प्रशंसा के पात्र हैं। मैं सारे वेतनभोगी लोगों की तरफ से, छोटे मझोले व्यापारियों की तरफ से, सीनियर सिटिजंस की तरफ से, महिलाओं की तरफ से, वैसे हमारी बहनों ने बजट पर बोलते हुए इस बात का उल्लेख किया है, उन सब की तरफ से आप धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन इस धन्यवाद में और जोड़ दीजिए और पे कमीशन की रिपोर्ट के विषय में एक स्पष्ट दिशा निर्देश देने की कृपा करिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत वित्त विधेयक और प्रस्तावों का पुरजोर समर्थन करता हूं।

SHRI P. CHIDAMBARAM: Mr. Deputy Chairman, Sir, I am grateful to the hon. Members and, especially, the Leader of the Opposition, Shri Jaswant Singh, for initiating this discussion on the Finance Bill. Mr. Jaswant Singh has sent me a note saying that 'he may not be present when I reply because of other commitments', and I quite appreciate that.

Sir, Mr. Jaswant Singh said that there must be a reform of the mindset. He was referring to the Ministry of Finance but I take it as a comment on the whole system of governance. I would support him in the argument that mindsets have to change. We no longer live in a world where we can say that we are isolated from what's happening in the rest of the world. The theory of decoulping India's economy from the rest of the world's economy is a fanciful theory. On an earlier occasion, I had explained that we are dependent on imports for a number of commodities, especially, crude oil, fertilisers, raw materials, minerals, metals, palm oil, etc. We have to pay for those imports and we can pay for those imports only if we export. So, imports are a necessity; exports are an imperative, and a country which has to increasingly trade with the rest of the world cannot claim to be not impacted or cannot hope to be not impacted from what's happening in the rest of the world. We live in a world where a number of forces are at play. The year 2008 has seen a number of crises hitting many countries of the world at the same time. There is a food crisis, there is a fuel crisis, there is a fiscal crisis in some countries and there is a financial crisis which seems to have affected a large number of financial institutions. While some of this was anticipated, and there is reference to these in the Budget Speech, some of this is completely un-anticipated; not only India, many countries did not anticipate this very sharp rice in commodities' prices and food prices. But if you read paragraphs 5, 6 and 7 of the Budget Speech, we had anticipated some of these pressures and taken pre-emptive action. We cut customs duties; we cut excise duties; we gave relief to Income Tax assessees, and we promises to take further fiscal and monetary measures if it became necessary. So, it may not be correct to say that we did not anticipate this turn of events. Paragraph 5, 6 and 7 of the Budget Speech, which I request you to read again, do refer to these aspects.

It is, therefore, important that our mindsets change so that we can bring to the governance of the economy a set of policies and principles that are relevant to the modern world. And these principles can only be based on an open polity and an open economy. We are proud about our open polity. We should be proud that our economy is also opening up, because it is the opening up of the economy, which was stated in 1991 by the then Finance Minister, and now the hon. Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, which has brought India to a stage where we can legitimately claim that we will be the fourth largest economy in the world in a few years, and that the prosperity of all Indians will rise as we continue to move up the economic ladder. Even today, we are regarded by the rest of the world as an important economy, a growing economy, a dynamic economy, which is the second fastest economy in the world. My hope and ambition is to become the fastest growing economy. When you say ' the second fastest growing economy', you are conceding the first place to another country, but our aim must be to become the fastest growing economy. At the same time, we recognize that growth is not an end. Growth is a starting point. The goal is, inclusive growth. No one of the side of the UPA or the Congress Party has even said growth is an end. Growth is a starting point. Growth is an imperative. Growth is necessary. But the ultimate goal is inclusive growth, where we can share the benefits of this growth with all the people of India. I believe that this Government, in the last four years, and this Budget and this Finance Bill, has taken a number of measures to make growth inclusive, and I shall briefly refer to them after I deal with the specific issues raised regarding the Finance Bill.

I am conscious that this is the last stage of the exercise of passing the Budget. I am grateful to hon. Members, especially the Chartered Accountant Members, who have pointed out a number of aspects of the Finance Bill, and I shall deal with them.

Sir, as far Sikkim is concerned, there is a debate that has been going on since 1990. It is a happy conclusion that we have reached an agreement with the Government of Sikkim. They have a Sikkim Subjects Register. Anyone who is on the Sikkim Subjects Register alone is entitled to buy property. The same Subjects Register will be operated and those who find their names in the Subjects Register will be exempt from Income Tax; all others would have to pay Income Tax. We have brought this amendment to reflect the agreement and even so, we have taken care to see that we are not reopening any assessments for any past years; we are making it prospective. So, Sikkim subjects will be exempt from Income Tax. Non-Sikkim subjects would have to pay Income Tax in the future. I do not think we should try to unravel that agreement. It has taken 18 years to reach that agreement; we should not unravel that agreement. In any event, I do not expect to collect very large revenues from even the non-subjects of Sikkim. I think we should let the matter rest there. Mr. Jaswant Sngh asked me, 'why are you limiting the Income Tax benefit to five years'? My short answer is, I am giving the Income Tax benefit for five years; they never had any benefit! We are giving an Income Tax benefit for five years, for hospitals that are located in two and three-tier cities. I think the hospital industry is happy that they will get a five-year Income Tax exemption. He also raised some concerns about 'fertilizer famine' coupled with fiscal improvements. I am surprised that the second Finance Minister of the NDA Government ended by quoting a Chancellor of Exchequer. I think, he was directing that comment not to his successor, but to his predecessor. I won't repeat that comment now. But how can the NDA Government claim to have been fiscally prudent compared to the UPA Government? The NDA Government inherited a fiscal deficit of 4.8 per cent and it worsened to 6.2 per cent and they closed their innings with the fiscal deficit of 4.5 per cent. So, after six years of NDA rule, the fiscal deficit came down from 4.8 per cent to 4.5 per cent. We brought down the

fiscal deficit to 3.1 per cent in the year that just ended and it will be 2.5 per cent by next year. I will deal with off-budget expenditure items presently. Likewise the NDA Government inherited revenue deficit of 3 per cent and it worsened to 4.4 per cent and when they closed their innings it was still 3.6 per cent. You inherited 3 per cent, you closed your innings with 3.6 per cent and claim to be fiscally prudent! We have brought down the revenue deficit from 3.6 per cent to 1.4 per cent in the year that is ended and will be 1 per cent next year. I think, in terms of fiscal prudence, leave out other issues, this Government has been the most fiscally prudent Government in India's history. For the first time, we have set for ourselves FRBM targets and we will meet those FRBM targets by the end of 2008-09.

Yes, there was a question about what happens if you take off-budget expenditure items. Even if you take off-budget expenditure, off-budget expenditure was incurred not for the first time. Off-budget expenditures were incurred even during the NDA period every year. Even if you take the off-budget expenditure, the fiscal deficit at the end of 2007-08 would be 3.3 per cent and revenue deficit at the end of 2007-08 would be 2 per cent. A vast improvement on what we inherited, namely, 4.5 per cent and 3.7 per cent respectively. So, by any measure, this Government is being fiscally prudent. The other phrase that was used, the alarming phrase was 'fertilizer famine'. Let me assure everyone in this House that there is no fertilizer famine and there will be no fertilizer famine. We have enough stock of urea. We produce fertilizers; we import fertilizers. This Government has given agriculture the highest priority. I quote Jawaharlal Nehru when he said, "Everything can wait except agriculture". This Budget, as well as the last Budget, was described by commentators as the green Budget. We will do nothing to hurt the farmer and we will do everything on our part to help the farmer, and if that means importing more fertilizers at higher prices, if that means encouraging Indian factories to produce more fertilizers and if that means bearing a higher fertilizer subsidy, every one of that willbe done and fertilizer will be made available to our farmers.

Sir, another question related to the PDS. We just received hot from the printing press the Report of the Standing Committee Food, Consumer Affairs and Public Distribution. On page 54, there is a chapter on the PDS. The conclusions of the Standing Committee, after referring to various reports, are at paragraph 4.72 onwards beginning at page 73. The opening sentence is this: "The Committee finds that the diversion of foodgrains meant for the poorest of the poor is the biggest menace in the functioning of the PDS. And, they go on to quote the extent of diversion. They have given numbers for each State. It will be embarrassing to many Members of the Council of States. Because each one of them represents a State, it will be embarrassing if I read out the extent of diversion in each State. So, I will not read it out. It is there on page 62. The point is: it is a shared responsibility. The responsibility of the Central Government is to give good procurement prices to the farmer, procure the foodgrains and allocate it to the States. The responsibility of the State Government is to ensure that there is no leakage, no diversion, no theft and the foodgrains reach the beneficiaries. This year, I am happy to inform this House that there has been a dramatic turnaround in the food situation in the last three weeks. We have already procured, as on day before yesterday, 134 lakh tonnes of wheat as against 76 lakh tonnes last year on the same date. We have already procured 229 lakh tonnes of rice as against 209 lakh tonnes last year on the same date. We are very confident we will exceed the producrement target of 150 lakh tonnes of wheat and we will also build a buffer stock and a strategic reserve. We have enough foodgrains. I want the people of this country to know that there are enough foodgrains in the country as a whole. There are enough foodgrains. There will be enough foodgrains in the public system and the public system is in a position to supply foodgrains

to ensure the availability of foodgrains for all the people of India. Let there be no doubt on that score at all. What about the supply to the PDS? Yes, there are complaints here and there from the States. These complaints will be addressed as our stocks improve. We are not discriminating against one State or another. Let me assure all the States, including Kerala from where complaints have come from hon. Members, that enough foodgrains will be given. Now, look at the record. During the six years of the NDA Government, the maximum off-take from the PDS, reflecting the supply of rice and wheat, was 239 lakh tonnes. In the first three years of the UPA Government-figures for 2007-08 and not fully available-we have had 300, 309 and 313 lakh tonnes of foograins. We have supplied, on an average, 70 lakh tonnes more foodgrains to the PDS. This year, I am confident, with the good harvest, good procurement, good public stock, enough foodgrains will be supplied to the people. But, then, after that, the responsibility is that of the State Government. That is what the Report says. It is the State Government which appoints the ration shop owner, or ration shop licensee, or manager; the State Government which inspects it; the State Government which controls it. The State Government must ensure that there is no diversion. If one-third of the foodgrains-39 per cent is what the Report says-are diverted, what does that mean? It means that to that extent, the poor are deprived. I am not running away from my responsibility. But, I want the Council of States to impress upon the State Governments their responsibility in ensuring that the foodgrains are distributed to the poor.

Sir, Mr. N.K. Singh, in his maiden speech, on which I compliment him-we have worked together for many years in many capacities-made a good intervention on the overall economic policy. I have no quarrel with that. He is of the same mindset as, I believe, I am. He called the Budget expansionary. Well, in a sense, it is. Because we anticipated the slowdown in the global output; we anticipated its impact on the Indian Economy. It is, perhaps, slightly expansionary. But our ambition is to grow at 9 per cent and reach 10 per cent growth at the end of the terminal year of the Eleventh Plan. So, we have to be expansionary. Yes, it is an expansionary Budget and such circumstances could also fuel inflation. But, there is inflation, as everybody knows, and as we have intervened in the earlier debate, it is both as a result of demand in some sectos, and as a result of supply shortages in other sectors. The demand side is being dealt with by appropriate monetary policy actions. the supply side is being dealt with by a number of administrative and fiscal actions. If is difficult year. It is a difficult year not only for India but it is difficult virtually for every country. I don't take any comfort in the fact, and I don't say this as an explanation or as an excuse, that India's inflation rate is lower than that of many other countries. I don't. Let me make that very clear. I am not happy about our inflation rate. But the fact is that this is, today, whether we like it or not, a global phenomenon. This is impacted by global rise in prices of food, fuel and commodities. Everybody is impacted. Countries which had inflation of one per cent or two per cent are now witnessing inflation of four per cent. But look at some other countries and the kind of inflation they have. Hungary has nine per cent; Russia has 7.4 per cent; Turkey has 10.9 per cent; Pakistan has 7.7 per cent; Venezuela has 18.5 per cent-actually, it was year on year-today, Venezuela has 29.1 per cent; Egypt has 14.4 per cent; and South Africa has 10.6 per cent. We have taken measures and we will take measures to control inflation. We will take fiscal measures, monetary measures and supply side measures to control inflation.

Mr. Trivedi referred to the new income-tax code. The income-tax code is ready. What is not ready is a discussion paper. I have not had the time to apply my mind to the discussion paper. Once the discussion paper is ready, I will certainly put the income-tax code in the public domain. Mr. N.K. Singh helped me put out one in 1998. Unfortunately, my successor

did not attend to it. But I will put another income-tax code in the public domain in the next couple of months.

The definition of charitable trust in section 2(15) has been amended in order to plug a loophole where businesses wearing the mask on disguise of charity are claiming exemption from income-tax. If a charity runs a business, it must pay income-tax. If a business runs a charity, the charity is exempted, but a charity cannot run a business and claim exemption. We are plugging a loophole.

As for the very of penalty without application of mind, it is a wrong reading of the section. I am willing to sit with Mr. Trivedi. There is an application of mind. There is a conclusion. A peculiar judgement said that you have to re-state the conclusion once again. The section is very clear.

On setlement Commission, unfortunately, our experience with the Income Tax settlement Commission has been very unsatisfactory. On the indirect tax side, the Settlement Commission has been able to reduce the pendency. But on the direct tax side, the pendency has been increasing at an alarming rate. Therefore, we have put a deadline and have said that if you are not able to dispose of a case within one year, the case will go the Assessing Oficer. It is not that anybody is being deprived of any opportunity. The Assessing Oficer will give the full opportunity. He will make an assessment. You can then go and appeal right through the hierarchy up to the Supreme Court. The Settlement Commission cannot become a place where you lodge your case and forget it for ten years and nobody can take action against you. Therefore, we have given a time-limit of one year.

On FBT earlier it was a disallowance method, I will explain it.The disallowance method was a discretionary method. FBT is a non-discretionary method and I think the industry has accepted it. There are no complaints from industry. I have not received any complaint from industry on FBT this year.

Finally, there were some questions about ousourcing income-tax activities. That is not correct. Income-tax functions are not being outsourced. The issue of PAN has been given to seleced agencies. But the issue of a PAN is a purely non-core function. The receipt of e-TDS returns, just the mechanical act of receiving the returns, and AIR returns and information relating to tax collections are being outsourced and this is being transmitted only to the Department. Core functions of assessment, etc. are entirely within the Income Tax Department. There is no intention of outsourcing it to anyone.

Finally, Sir, there was a complaint that we were not transferring enough money to the States. I am surprised by this. Never, in India's history, has so much money been given to the States. Never. I am willing to debate it. Time is limited today. Let us have a public debate. Please come and let us debate the numbers. In 2003-04, the State's share of duties and taxes was Rs. 65,784 crore. This year, we will give to the States Rs. 1,78,765 crores. That is the constitutional right of the States I am not claiming any act of generosity. The resson why I said it a constitutional right is because I am collecting more and giving them more. Now what is left to the Centre, what I get, what entirely belongs to the Centre, what we give out of that, is called a grant. That is entirely discretionary, discretionary in the sense that the Planning Commission, the Finance Ministry, the Prime Minister, they discuss with the Chief Ministers, we give them money. We should. After all, the States can alone implement the programme. Now, look at the number. This is not a constitutional right. This is a grant out of the money left to the Centre. In 2003-04, we gave to the States, in terms of grant, Rs. 47,320

crores. This year, we will give Rs. 1,24,546 crores. Never before in India's history has so much money been given to the States, and that is why, the fiscal health of the States has never been better than what it is today. All States put together on the 26th of April, had cash balances of Rs. 73868 crores, twenty five States are in revenue surplus, all States put together, are in revenue surplus. The fiscal deficit of all States put together is only 2 per cent.

Finally, Sir, there was some reference to CTT. CTT is a mirror image of STT. The same arguments were put forward when I introduced STT. Today, everybody accepts STT as a legitimate levy which has brought about some lessening of volatility in the equity market. CTT will have the same impact. There is CTT in many other countries. When anything new is introduced, obviously, there will be some resistance and criticism. But I am now an old war horse in this game. We will live with criticism for a while, but I assure you that it will be accepted.

Sir, let me conclude by saying that his Government had done more for inclusive growth than any other Government. NREG, RTI, Aam Aadmi Bima Yojana, the National Rural Health Mission, the Swasthaya Bima Yojana, the vast expansion of Sarva Shiksha Abhiyan, huge allotment to the Mid-day Meal scheme, all this is intended to be for inclusive growth, and this Budget takes the process of inclusive growth, a step forward, and I am sure that even if growth slows down this year to some extent, it may not be 9 per cent, but it will still be between 8 and 9 per cent. That will still keep us the second fastest growing economy in the world, and when the 5 year term of this Government comes to an end, when you look back, you will say that this Government raised India's growth rate to a new level and brought about a new dimension to inclosive growth. With these words, I conclude.

SHRI S.S. AHLUWALIA (Jharkhand): Sir, I have a small question. Sir, he mentioned about Sikkim. Sir, I would like to know about Sikkim only. He mentioned about Sikkimese and non-Sikkimese. The difinition of Sikkimese and non-Sikkimese is a very wide definition. Sir, the day Sikkim became a part of the Union, those who were living there, they were from the plains. There are only 400 to 500 families. Will you allow them all tax exemptions or give them the same exemption status, the same exemptions which you are going to give to the Sikkimese? They were with them. They are part of the subject register. But as per the new Income-tax Act amendment, they are not getting this benefit.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, I have clarified it, the definition of the term Sikkimese is based on the register of Sikkim subjects, maintained under the Sikkim Subjects Regulation 1961, read with the Sikkim Subject Rules 1961 and Government orders issued in that regard. The Government of Sikkim follows the same register and Government orders while issuing certificates of identification to the residents of Sikkim which enables the holders of those certificates to purchase land or seek employment in Government service in Sikkim. If anybody's name is found in the Sikkim Subjects Register made under the Sikkim Subjects Regulation, he will be entitled to the benefit.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, I shall put the motion regarding the Appropriation (No. 2) Bill, 2008 to vote.

The question is:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2008-09, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 *to* 4 *and the Schedule were added to the Bill.*

Clause 1, *the Enacting Formula and the Title*

were added to the Bill.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, I move:

"That the Bill be returned."

The question was put and the motion

was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the motion regarding the consideration of the Financial Bill, 2008 to vote.

The question is:

"That the Bill to give effect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 2008-09, as Passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now taken up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 125 *and the First Schedule to the Ninth Schedule were added to the Bill.*
Clause 1, *the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, I move:

"That the Bill be returned."

The question was put and the motion was adopted.

श्रीमती सुषमा स्वराज (मध्य प्रदेश): उपसभापति जी, प्रधान मंत्री जी जा रहे हैं। कल हमें संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था कि जो विषय नेता प्रतिपक्ष ने उठाया था, उसका जवाब ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: मुरली देवरा जी बोलेंगे।

श्रीमती सुषमा स्वराज: उन को रोकिए, प्रधान मंत्री जी जा रहे हैं। ...(**व्यवधान**)....

डा॰ वी॰ मैत्रेयन (तमिलनाडु): प्रधान मंत्री जी, सदन में आइए ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: मुरली देवरा जी का subject है, वह बोलेंगे। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: मुरली देवरा जी को हम सुनेंगे ही नहीं ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is a subject relating to the Petroleum Ministry. The Petroleum Minister is here. He is going to answer it. ...*(Interruptions)*...

श्रीमती सुषमा स्वराज: सर, जिस व्यक्ति ने संसद की अवमानना की है, उस मंत्री को नहीं सुनेंगे ....(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Deora is going to reply. Please listen to him. ...(*Interruptions*)...

STATEMENTS BY MINISTERS (*Contd.*)

Issues raised By Hon'ble Leader of Opposition concerning Minister of Shipping, Road Transport and Highways

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI MURLI DEORA): Sir, the Ministry of Petroleum & Natural Gas had made allocations of 10,000 cubic metres of gas per day to M/s Kings India Chemicals Corporation Limited and 4.5 lakh cubic metres of gas per day to M/s Kings India Power Corporation Limited. ...(*Interruptions*)...

श्रीमती सुषमा स्वराज (मध्य प्रदेश): जिस मंत्री ने संसद की अवमानना की है, impropriety commit की है...

श्री उपसभापति: कहां की है? ...(व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: संसद में बोलने के बजाय संसद के बाहर बयान दिया है। उस मंत्री को हम ....(व्यवधान)...

SHRI MURLI DEORA: Sir, the Prime Minister's Office has not issued any order or any instructions to help the Company. Certain references were received from Prime Minister's Office in a routine manner without any recommendation on the basis of a representation made by Shri Selvakumar Baalu, Director of the Company. ...(*Interruptions*)...

Sir, the Companies filed writ petitions in the Madras High Court against the cancellation of agreed allocation of gas. ...(*Interruptions*)... A learned Single Judge, by order, dated 10th October, 2007, passed the following orders:—

> "The first respondent herein is directed to afford reasonable opportunity to the petitioner herein and thereafter made re-allotment in favour of the petitioner on the basis of the priority. This exercise can be done within a period of four weeks from the date of receipt of a copy of this order". ...(*Interruptions*)...

Since the order of the single Judge was not implemented, the company filed a Contempt Petition. In the meanwhile, Tamil Nadu Power Producers Association and Narimanam Zone Natural Gas Consumers Association filed Writ Appeals, W.A. No. 241 and 244 of 2008, against the orders of the Learned Single Judge, dated the 10th October 2007, in Writ Petitions Nos. 29602 and 32441 of 2005, before the Division Bench of the Madras High Court. Union of India, GAIL and the Companies were parties. The Division Bench of the hon. High Court of Madras passed an order in the Writ Appeal, on 19.02.2008, wherein the earlier order passed by the Single Judge on 10.10.2007 was set aside and the Government was directed to decide upon the applications on the firms on merit. ...(*Interruptions*)...

In the meanwhile, one independent Power Producers Association and others have filed a Writ Petition, Civil No. 9595 of 2007, in the High Court of Delhi, wherein the same subject matter of allocation of gas in involved and a stay order was issued by the aforesaid High Court. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Maitreyan, this is Parliament ...(*Interruptions*)... This is Parliament. ...(*Interruptions*)... It is everyone's responsibility, it is our responsibility